कैं0आलोक शेखर तिवारी, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,

अकादिमक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—3

देहरादून,

दिनांक:2.4-नवम्बर, 2017

विषय:

प्रदेश के डाइट्स में निर्माणाधीन बहुउद्द्वेशीय कक्षों के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या—एससीईआरटी / 4157—59 / VIII—1(02)—4शि.शि० / 2017—18 दिनांक 06 सितम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या—एससीईआरटी / 4771—72 / VIII—1(02)—4शि.शि० / 2017—18 दिनांक 07अक्टूबर, 2017 तथा वित्तीय रवीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—610 / 3(150) / XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—1110 / XXIV—3 / 16 / 02(201)15, दिनांक: 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश के 10 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में बहुउद्देशीय कक्षों के निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण लागत रूपये 620.74 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 250.89 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख नवासी हजार मात्र) की धनराश अवमुक्त की गई थी। उक्त 10 डायट्स में से 06 डायट्स द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत 6 डायट्स हेतु कुल अवशेष धनराशि रूठ 237.94 लाख में से प्रिशिष्ट—अ की तालिका के स्तम्य—8 के अनुसार रूठ 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्ती प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं—

2-

- (1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं,अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
  - (2) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
  - (3) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
  - (4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि०द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
  - (5) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
  - (6) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047 / xIV 219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (8) आगणन गिठत करते समय तथा कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (9) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- (10) उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610 / 3(150) / XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के अनुसार निर्धारित प्रपंत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए डाइटों के समस्त कार्यों को

समयबद्ध रूप से समयसारिणी बनाते हुए निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए भवनों को विभाग को हस्तगर कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलंब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथ बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व

मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य यह में जारी होने वाले शासनादेशों क विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

स्वीकृत धनराशि के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते

हुए उक्त की एक प्रति भारत सरकार एवं राज्य योजना आयोग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 के अनुदान सं0 11— आयोजनागत के अधीन 4202-शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 202-मध्यमिक शिक्षा, 19-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भवन निर्माण के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा। यह आदेश वित्त बिभाग के शासनादेश संख्या—610/3(150)/ XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में प्रदत्त निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(कै0आलोक शेखर तिवारी) अपर सचिव।

## पृष्ठांकन संख्या:— 1357/XXIV-3/17/02(201)2015 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, नई दिल्ली।

आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी। 3--

समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। 4-

निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।

समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। 6-

7-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय। 8-

वित्त अनुभाग-3 / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन। 9--

सम्बन्धित प्राचार्य डायट्स, उत्तराखण्ड। 10

गार्ड फाइल। 11-

> ्आज्ञा से ाउप सचिव।

## सासनादेश संख्या—1357 / XXIV-3/2017-2(201)/2015, दिनोंक 24 अक्टूबर, 2017 का संतरनक:—

	યાગ		374.56	22.38	396.94	159.00	200.00
6	डायट रतूडा, रूद्रप्रयाग योग	उ0पेयजल निर्माण निगम	71.54	03.62	75.16	30.00	35.155
5	डायट रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	उ0पेयजल निर्माण निगम	49.37	00.63	50.00	20.00	30.00
4	डायट, गौचर, चमोली	उ०पेयजल निर्माण निगम	71.54	03.62	75.16	30.00	35.155
3	डायट, चड़ीगांव, पौड़ी	उ0पेयजल निर्माण * निगम	68.40	05.56	73.96	30.00	34.00
2	खायट रूड़की(हरिद्वार)	उ०पेयजल निर्माण निगम	48.14	04.55	52,69	21.00	31.69
1.	डायट, नई टिहरी	उ०पेयजल निर्माण नियम	65.57	04.40	69.97	28.00	34.00
1	2	3	4	5	6	. 7	8
\ \times			टाठएठसाठ द्वारा सिविल निर्माण कार्यो हेतु	निर्धारित औचित्यपूर्ण जत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली ,2017 में उल्लिखित कार्यों हेतु	लागत कुल ओचित्यपूर्ण लागत	वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017—18 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
क	र्भस्थान का नाम	कार्यदायी संस्था	T-A	0.10 %			नराशि लाख में

(रूपये दो करोड़ मात्र)

्रिक्षिमा) उप सचिव।